भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

सार्वजनिक माफीनामा **20 मार्च, 2014**

12 अप्रैल 2014 को बीजापुर जिले के कुटरू के पास हमारी पीएलजीए के द्वारा पुलिस होने की गलत फहमी में किए गये बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में हुई मतदान दल के कर्मचारियों की दुखद मौत पर हमारी पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मृत व घायल कर्मचारियों के परिवार जनों, बंधु–मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करती है और इस गंभीर गलती के लिए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है। साथ ही संजीवनी वाहन को उड़ाने की घटना में मृत ड्रायवर एवं टेक्नीशियन के परिजनों के प्रति भी हम संवेदना प्रकट करते हैं। घायल कर्मचारियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हूए हम उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वे उनके इलाज में कोई कसर न छोड़े। हमारी इस चूक की वजह से घटना में मृत 7 शिक्षक–कर्मचारियों के परिवारजनों को अपूरणीय क्षति पहुंची है जिसका हम कोई भरपाई नहीं कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि गलती कहने और माफी मांगने मात्र से दिवंगत शिक्षक–कर्मचारी वापस नहीं आ सकते। हम सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मृत शिक्षक व कर्मचारी हमारी पार्टी के दुश्मन नहीं थे और न ही हमने उन्हें जानबूझकर मारा। यह असावधनी और धेखे से हुई दुर्घटना है।

प्रथम दृष्टि में यह लगता है कि गलत फहमी पैदा करने के पुलिसिया दाव–पेच जैसे गाडियां बदलना, सिविल वाहनों का इस्तेमाल आदि के चलते अनजाने में, गलत फहमी व जल्दबाजी में हमारी ओर से यह भारी चूक हुई है। यह एक चिंताजनक व अफसोसनाक घटना है। इसे हम गंभीरता से लेंगे। हालांकि चुनाव पूर्व ही हमारी स्पेशल जोनल कमेटी ने एक परिपत्र जारी करके पुलिस पर की जाने वाली सैनिक कार्रवाइयों के दौरान मतदान दलों, नागरिकों व जनता के जानमाल को नुकसान न पहुंचने देने आवश्यक व तमाम सावधानियां बरतने हमारे कैडरों को दिशा–निर्देश दिया था। बावजूद हमसे यह भारी चूक हुई है। यह चूक कैसे, क्यों, किस स्तर पर हुई है, इसकी गहराई से जांच–पड़ताल करके नतीजों पर आधारित होकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने उचित कदम उठायेंगे।

इस घटना की कड़ी निंदा करने वालों में मृतक व घायलों के परिजनों, शिक्षाकर्मी व कर्मचारी संगठनों से लेकर विभिन्न संसदीय पार्टियां, आला पुलिस अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ सरकार व केंद्र सरकार तक शामिल हैं। इनमें से परिवार जनों, शिक्षक–कर्मचारी संगठनों के रोष व आक्रोश को हम समझ सकते हैं लेकिन शोषक–शासक वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाली लुटेरी केंद्र–राज्य सरकारों, उनके राज्ययंत्र के कल–पुर्जे का काम करने वाली पुलिस के अधिकारियों व संसदीय पार्टियों को हमारी निंदा करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। इस दुखद घटना का फायदा उठाते हुए पुलिस अधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्रालय हमें उग्रवादी करार देने और इस कार्रवाई को जानबूझकर मतदान दल को निशाना बनाकर की गयी कार्रवाई साबित करने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। जनविरोधी, देशद्रोही, भ्रष्ट व फासीवादी कांग्रेस, भाजपा व संघ परिवार के सदस्य संगठनों के द्वारा हमारे खिलाफ रैलियां आयोजित की जा रही हैं। दरअसल शोषक–शासक वर्गो– दलाल बड़े पूंजीपति वर्ग, सामंती वर्ग एवं उनके साम्राज्यवादी आकाओं की सरकारें ही असली आतंकवादी व उग्रवादी हैं जो हर दिन उत्पीड़ित– शोषित जनता को आतंकित करने में लगी रहती हैं। जल–जंगल–जमीन पर अपने अधिकार, अपने आस्तित्व व आस्मिता के लिए संघर्षरत जनता पर नाजायज युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट थोपने वालों को हमारी गलती पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ढाई साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़ों तक को मारने वाल, एड़समेट्टा, सारकेनगुडा जैसे दसियों नरसंहार करन वाले, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार व हत्या करन वाले, घरों–गांवों को जलाने वाले, ग्रामीणों की बेदम पिटाई करन वाले, अवैध गिरफ्तारियां करके फर्जी केसों में जेल भेजन वाले, बिना या फर्जी गवाही पर लंबी सजाएं देने वाले ही असली उग्रवादी हैं। देश की संपदाओं को बहुरष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने वाले ही असली देशद्रोही हैं।

हमारी ओर से शिक्षक–कर्मचारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का सवाल ही नही उठता है। यह जगजाहिर है कि शिक्षक–कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार जिन्हें पेट्टी बुर्जुआ वर्ग कहते हैं हमारे नवजनवादी संयुक्त मोर्चे के चार वर्गो में से हैं। ये हमारे मित्र वर्ग के हैं। ऐसे में इन पर हमले के बारे में हमारा कोई भी कैडर सोच भी नहीं सकता है। जबकि सरकारों की शिक्षक–कर्मचारी विरोधी नीतियों से सभी वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, संघर्ष इलाकों में मतदान कराने के लिए शिक्षक–कर्मचारियों को निलंबन या बर्खास्तगी का डर दिखाकर उनके विरोध के बावजूद एवं उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन भेजा जाता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम पर अलोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराये जाते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के नाम पर विगत नवंबर में 72 हजार अतिरिक्त फोर्स सहित कुल डेढ़ लाख सशस्त्र बलों की संगीनों के साये में जनता को आतंकित करके

छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों को संचालित किया गया था। हमारी पार्टी के चुनाव बहिष्कार के आव्हान को विफल करने अब लोकसभा चुनावों में भी दसियों हजार सशस्त्र बलों को तैनात करके चुनाव के दो महीने पहले से ही लगातार गश्त अभियान चलाते हुए, गांवों पर हमले करते हुए जनता में खौफ फैलाया गया था। चुनाव बहिष्कार के अपने जनवादी अधिकार से जनता को वंचित रखने के तहत ही यह सब किया गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव बहिष्कार के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने जनता के सामने प्रतिरोध का रास्ता चुनने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। जनता के हक में जारी इस प्रतिरोध में हमारे निशाने पर सरकारी सशस्त्र बल थे। यहां यह बताना भी उचित व आवश्यक है कि पुलिस, अर्ध–सैनिक बल व सेना के जवान एवं छोटे अधिकारी भी वर्गीय आधार पर हमारे दुश्मन नहीं है और न ही उनके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी है। लेकिन शोषक–शासक वर्गो के राज्ययंत्र के हिस्से के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने के कारण ही हम मजबूरन उन्हें निशाना बनाते हैं।

हम मृतक व घायलों कि परिवार जनों, बधु–मित्रों, शिक्षक–कर्मचारी संगठनों, जनता, प्रगतिशील–जनवादी ताकतों, मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हैं कि वे हमारे इस स्पष्टीकरण को समझने की कोशिश करे कि कुटरू की घटना इरादतन घटना नहीं है। इसे मानवाधिकारों के हनन के रूप में न देखें। सरकारों के द्वारा जनता पर जारी नाजायज युद्ध के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीड़ित जनता के द्वारा किये जा रहे न्यायपूर्ण जन युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के षड्यंत्रकारी दाव–पेच को सामझने में हमारी ओर से हुई खामी व कमी के चलते घटी गंभीर गलती के रूप में इसे देखना चाहिए। हम कम्युनिस्ट मनुष्य के प्राणों को मूल्यावान व सर्वोपरि समझते हैं। दुनिया के तमाम मनुष्यों की खुशहाली के लिए, शोषण व उत्पीड़न मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना के लिए शोषकों–उत्पीड़कों के खिलाफ हम जन युद्ध में लगे हुए हैं और इस दौरानं सर्वोच्च बलिदान देने तैयार रहते हैं।

अंततः इस तरह की घटनाओं की जवाबदेही लुटेरी सरकारों पर ही होगी। जब तक चुनाव में वोट देने या न देने सहित जनता को उनके तमाम जनवादी अधिकारों से लैस नहीं किया जाता है, जनता का शोषण–दमन खत्म नहीं किया जाता है तब तक जन प्रतिरोध व जनयुद्ध जारी रहेगा। सशस्त्र बलों की भारी तैनाती के बगैर जनवादी माहौल में यदि चुनाव कराये जाते हैं तो इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी।

हम शिक्षक–कर्मचारियों व पत्रकारों से अपील करते हैं कि वे पुलिस वाहनों में, पुलिस के साथ, पुलिस के द्वारा इस्तेमाल वाहनों पर सफर न करें। साथ ही हम निजी वाहन मालिकों से अपील करते हैं कि वे संघर्ष इलाकों में पुलिस को लाने–ले जाने का काम न करें। अपने वाहनों में न बैठायें अपने वाहनों को पुलिस विभाग के लिए किराये से न दें। पुलिस के द्वारा संजीवनी वाहन का जबरन इस्तेमाल के चलते वाहन ड्रायवर एवं तकनीशियन की अनावश्यक मौत हो गयी। निजी व सरकारी विभागों के वाहनों के जबरन अधिग्रहण के संदर्भ में वाहनों के ड्रायवरों को पुलिस के साथ ड्यूटी में न जाने हम आग्रह करते है।

मतदान कर्मियों या पुलिस जवानों की मौत पर सरकारें मगरमच्छ की आंसू बहाती हैं, मुआवजे के रूप में मुठ्ठी भर रूपये देती हैं, सांत्वना के दो–चार शब्द बोलती हैं और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए जान देने वाले शहीद कहकर पल्लाझाड़ लेती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान लोकतंत्र झूठा है। यह शोषण मूलक अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था है। शिक्षक–कर्मचारी, सशस्त्र बलों को ये शोषक–शासक वर्ग व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें महज अपनी सेवा करने वाले व सुरक्षा देने वाले मोंहरे समझते हैं। अपने शोषण व शासन को जारी रखने के लिए ये किसी की भी बलि चढ़ाते हैं। उनकी मौत पर उन्हें कोई अफसोस नहीं होता है। जन धन के कुछ हिस्से को खर्च करके, उनकी जनविरोधी नीतियों के चलते बने बेरोजगारों की फौज से कुछ नये लोगों को अपनी सेवा में फिर से भरती करते हैं। हम परिवारजनों, कर्मचारी संगठनों से अपील करते हैं कि वे इस सच्चाई को समझें एवं जन आन्दोलनों व जन युद्ध के पक्ष में खडे होवें।

गुड्सा उसेंडी

प्रवक्ता,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)